सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹ 02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, मंगलवार , 27 मई, 2025
वर्षः 02, अंकः 148, पृष्ठः 8+4

इनसाइड दोस्तों को जमकर शराब पिलाई.. उन्हीं ने छत से फेंक दिया » Pg11

हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली डॉक्टर अनुष्का तिवारी का सरेंडर

» Pg03

अब दूरी के हिसाब से देना होगा टोल टैक्स

» नई दिल्ली/प्रमुख स्वराज इंडिया

केन्द्र सरकार राजमार्ग पर सफर कर रहें यात्रियों के सफर को अधिक किफायती और सुविधापूर्ण बनाने जा रही है । एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार नई टोल नीति के तहत वाहन मालिक जल्द ही वार्षिक फास्टैग का विकल्प चुन सकेंगे और 3000 सालाना 3000 रुपए चुका कर राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर अनलिमिटेड यात्रा कर सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई टोल नीति पर कार्य कर रहा है।नई टोल व्यवस्था के अनुसार सरकार दोहरी भुगतान प्रणाली पर विचार कर रही है। जिससे वाहन चालकों को 3000 हजार रुपए का वार्षिक पास पास और यात्रा की दूरी के हिसाब से टोल चुकाने की विकल्प दिया जाएगा।

» केंद्र सरकार कर रही नई टोल नीति पर विचार

» नई टोल नीति के तहत वाहन मालिक जल्द ही वार्षिक फास्टैग का विकल्प चुन सकेंगे

» 3000 सालाना रुपए चुका कर राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर अनलिमिटेड यात्रा कर सकेंगें

ये हैं वो दो तरीके जिनपर होगा निर्णय

वार्षिक पास–नई टोल नीति के अनुसार सभी प्राइवेट वाहन चालक फास्टैग में सालाना 3000 हजार रुपए का रिचार्ज करवा कर, पूरे साल बिना किसी परेशानी के एक्सप्रेस वे और राजमार्ग पर यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पहले उस प्रस्ताव को रद्द कर था। जिसमें वाहन चालकों को पंद्रह सालों के लिए 30 हजार की लागत वाले आजीवन फास्टैग का सुझाव दिया गया था।

दूरी आधारित टोल

–पुरानी टोल व्यवस्था के अनुसार पहले वाहन चालकों को थोड़ी दूरी के लिए भी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। लेकिन नई टोल नीति के अनुसार अब निजी वाहन चालक 50 रुपए प्रति 100 किलोमीटर के हिसाब से यात्रा कर सकते हैं।विभागीय सूत्रों के अनुसार मंत्रालय को कई शिकायतें मिली थी कि हमारा घर टोल प्लाजा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है जिस कारण हमें बार बार टोल से होकर गुजरना पड़ता है।जिसके बाद सरकार इस पर विचार कर रही है।

नए सिस्टम से टोल से मिल सकती है कुछ राहत

केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि टोल बूथों को खत्म कर, उसकी जगह सेंसर आधारित टोल प्रणाली स्थापित करना है। नई व्यवस्था से अब वाहन चालकों को टैक्स चुकाने के लिए टोल चुकाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अगर यह नीति हो जाती है तो इससे यात्रा बाधा रहित और यात्रा में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। साथ ही जो रोजाना काम के चलते सड़क का प्रयोग करते हैं उनको कुछ हद तक राहत भी मिलेगी। इस पर केंद्र सरकार लगातार प्रयोग कर रही है।

छात्रा का यौन उत्पीड़न करने वाला प्रोफेसर निलंबित

» प्रोफेसर दुष्यंत कुमार को 24 मई को छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था

कोर्ट से खारिज हुई जमानत

» मुजफ्फर नगर/ स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में छोटूराम डिग्री कॉलेज की प्रबंधन समिति ने एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद इस शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर दुष्यंत कुमार को निलंबित कर दिया है। एक पदाधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कॉलेज प्रबंधन के सचिव शरद कुमार ने बताया कि छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद बुलाई गई एक आपात बैठक में इस कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया गया।

उन्होंने बताया कि एक उप समिति घटना की जांच

करेगी। इस बीच, मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर दुष्यंत कुमार की जमानत याचिका स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत अनुरोध को खारिज कर दिया। अभियोजन अधिकारी केसी मोरी के अनुसार, दुष्यंत कुमार को 24 मई को छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म) और 62 (आजीवन कारावास का प्रावधान) भी जोड़ दी हैं।

इसके पहले पुलिस ने प्रोफेसर दुष्यंत कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान), 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था। कॉलेज की बीएससी की छात्रा ने शनिवार को कॉलेज के प्लांट पैथोलाजी विभाग के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

पीएम की सुरक्षा को लेकर हाई प्रोटोकॉल रहेगा

» कानपुर पहुंचे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं

» 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर शहर आ रहे हैं

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। एसपीजी और एनएसजी के साथ समन्वय स्थापित कर सुरक्षा घेरा मजबूत करें। मगर राहगीरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए यातायात व्यवस्था बाधित न करें। गर्मी को देखते हुए पानी का विशेष इंतजाम करें। पीएम के कार्यक्रम के दौरान पूरे शहर में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाएं।

30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर आ रहे हैं। वे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के मैदान पर जनसभा करेंगे और 21 हजार करोड़ रुपये की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। पीएम कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सोमवार सुबह प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार हेलीकॉप्टर से कानपुर पहुंचे और सीएसए विवि का निरीक्षण किया। उन्होंने जनसभा स्थल पर पंडाल, मंच के साथ पार्किंग, जनप्रतिनिधियों के बैठने, आम जनता के बैठने आदि जगहों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने गर्मी को देखते हुए पानी का विशेष इंतजाम करने का निर्देश दिया। पंडाल के हर ब्लॉक में पेयजल की व्यवस्था की जाए। पार्किंग अधिक से अधिक बनाई जाए, जिससे न तो जाम की स्थिति उत्पन्न हो और न ही लोगों को गर्मी में जनसभा स्थल तक पहुंचने में अधिक चलना पड़े। जनता के लिए एलईडी भी लगाई जा रही है, जिससे कोई दिक्कत न हो। वहीं, जनसभा स्थल में प्रवेश के लिए तीन द्वार बनाए जा रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए हर ब्लॉक पर कूलर लगाए जाएं। इस मौके पर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार, मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडियन, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे।

विवि में बन रहे पांच हेलीपैड, 25 पार्किंग

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य सचिव को बताया कि पीएम कार्यक्रम के लिए विवि में पांच हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। विवि के कुलपति कार्यालय के सामने बने तीन हेलीपैड पीएम को लेकर रिजर्व रहेंगे। वहीं, जनसभा स्थल के सामने मैदान में दो नए हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। जनसभा स्थल के चारों तरफ कुल 25 पार्किंग बनाई जा रही है। जिसमें 1000 बस, 1000 कार और दोपहिया वाहनों के खड़ा होने का इंतजाम किया गया है।

एंबुलेंस, डॉक्टर और दवाओं का रखें विशेष इंतजाम

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एचबीटीयू स्थित संयुक्त आयुक्त, उद्योग कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चल रही तैयारी की बारीकी से समीक्षा की। कहा, कार्यक्रम स्थल पर पेयजल, मोबाइल ट्वायलेट तथा स्वास्थ्य सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये। गर्मी को देखते हुए एंबुलेंस, चिकित्सक और दवाओं का विशेष इंतजाम रखें।

पूरे शहर में चलाएं स्वच्छता अभियान

सीएसए विवि परिसर में चल रही साफ-सफाई को देखते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पूरे जिले में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। कहा, ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से स्वच्छता अभियान चलाएंगे।

हॉस्टल में छात्रों के साथ रहेंगे वार्डन

सीएसए विवि के कुलपति डॉ. आनंद कुमार सिंह ने बताया कि पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सोमवार को सभी डीन व विभागाध्यक्ष के साथ बैठक की गई है। जिसमें सभी को निर्देश दिया गया है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सभी छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में रहेंगे। वे बिना काम के गैलरी में चहलकदमी नहीं करेंगे। इस दौरान वार्डन भी अपने हॉस्टल में उपस्थित रहेंगे। कुलपति ने बताया कि हॉस्टल में रह रहे सभी छात्र-छात्राओं की सूची वार्डन से मांगी गई है। विवि में भी स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षकों के साथ छात्र-छात्राएं भी श्रमदान करेंगे।

किया कैरेंस क्लाविस का कानपुर में भव्य अनावरण टेस्ट ड्राइव

» खन्ना किया की ओर से विशेष बुकिंग ऑफर की सुविधा उपलब्ध

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। उत्तर प्रदेश में प्रीमियम ऑटोमोटिव अनुभव का एक विश्वसनीय नाम, खन्ना किया ने आज अपने अत्याधुनिक शोरूम में किया कैरेंस क्लाविस के बहुप्रतीक्षित लॉन्च की घोषणा की।

कैरेंस क्लाविस, किया की बहुउपयोगी कैरेंस श्रृंखला में एक शानदार नया मॉडल है, जो एमपीवी की उपयोगिता और एसयूवी के दमदार अंदाज़ का बेहतरीन मिश्रण है। यह वाहन आधुनिक भारतीय परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो स्थान, सुरक्षा और स्टाइल ऑलइनवन पैकेज में चाहते हैं। यह लॉन्च खन्ना किया के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो विश्व स्तरीय ऑटोमोटिव नवाचारों को उत्तर प्रदेश के हर दिल तक

पहुँचाने के संकल्प को दर्शाता है।

इस अवसर पर अभिरूप खन्ना, निदेशक, खन्ना ऑटो केयर प्रा. लि. ने कहा कि हमें किया कैरेंस क्लाविस को अपने शोरूम में प्रस्तुत करते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है। इसके उत्कृष्ट डिज़ाइन, अत्याधुनिक कनेक्टिविटी और मजबूत सुरक्षा विशेषताओं के साथ, हमें विश्वास है कि क्लाविस शहरी परिवारों की गतिशीलता की परिभाषा को ही बदल देगा। खन्ना किया हमेशा की तरह बेहतरीन उत्पाद और सर्वोतम सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। किया कैरेंस क्लाविस की प्रमुख विशेषताएँ पर प्रकाश डालते हुये उन्होंने बताया कि इसमें आधुनिक एसयूवी डिजाइन, स्मार्ट स्टोरेज के साथ विशाल 3-रो सीटिंग, ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट के साथ नया किया कनेक्ट , उन्नत सुरक्षा सुविधा - 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड, टर्बो पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन विकल्प में उपलब्ध है।इस अवसर पर प्रमुख रूप से पुनीत खन्ना, श्री सुमित खन्ना, महाप्रबंधक श्री संजय तथा शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे ।

सिर्फ एक मिनट की देरी पर एग्जाम सेंटर का गेट बंद

» 9 बजे से पेपर शुरू था लेकिन 8:31पर एंट्री रोकी, कई छात्र वंचित

» छात्रों और अभिभावकों ने जताया विरोध

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सीयूईटी यूजी एग्जाम को लेकर मंगलवार को पेपर था लेकिन आरोप हैं कि परीक्षा केंद्र में मनमानी के चलते कई स्टूडेंट्स एंट्री से वंचित रह गए। कल्याणपुर निवासी रामनरेश सिंह ने बताया कि वह मंगलवार सुबह अपनी भांजी को CUET UG परीक्षा दिलाने MD Infotech परीक्षा केंद्र (श्यामनगर, कानपुर) पहुंचे थे। उनका कहना है कि पेपर का समय सुबह 9:00 बजे था, लेकिन परीक्षा केंद्र का गेट 8:31 पर ही बंद कर दिया गया।

रामनरेश सिंह के अनुसार, उनकी भांजी केवल एक मिनट की देरी से पहुंची थी, इसके बावजूद उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। सिर्फ उनकी भांजी ही नहीं, कई अन्य छात्र-छात्राएं भी इसी वजह से परीक्षा देने से वंचित रह गए। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र पर न तो कोई पुलिस मौजूद थी, न ही कोई पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था।छात्रों और अभिभावकों ने इस घटना को छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। वही, रामनरेश सिंह के आरोप हैं कि इस मामले में डीएम कानपुर को भी फोन किया गया तो उन्होंने एडीएम से बात करने को कहा। एडीएम अमरनाथ उपाध्याय ने भी कई नियमों की बात कहते हुए मदद करने से इंकार कर दिया।

हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली डॉक्टर का सरेंडर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। ट्रांसप्लांट के बाद दो इंजीनियरों की मौत की जिम्मेदार मानी जा रही डॉ. अनुष्का तिवारी ने पुलिस की आंखों में धूल झोंककर सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अनुष्का तिवारी 18 दिन से फरार थीं। आरोप है कि दांतों की डॉक्टर अनुष्का ने इंजीनियर विनीत दुबे और मयंक कटियार का हेयर ट्रांसप्लांट किया था। ट्रांसप्लांट के कुछ ही घंटों के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी। दोनों का चेहरा सूज गया था और 24 घंटे में दोनों इंजीनियरों ने दम तोड़ दिया था। परिजनों ने डॉ. अनुष्का के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

डॉ. अनुष्का ने सोमवार को पुलिस को चकमा देते हुए सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) सूरज मिश्रा की कोर्ट में सरेंडर किया। अनुष्का अपने पति सौरभ त्रिपाठी के साथ कोर्ट पहुंची। उनके साथ 2 वकील भी थे। अनुष्का अपना चेहरा दुपट्टे से ढके थी। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। डीसीपी वेस्ट ने बताया कि पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर अनुष्का से पूछताछ करेगी। क्लीनिक की तलाशी भी की जाएगी।

जेल जाने तक लगातार रोती रही

अनुष्का कोर्ट में हाजिर होने से लेकर जेल जाने तक लगातार रोती रही। पति सौरभ त्रिपाठी अनुष्का को गले लगाकर भरोसा दिलाते रहे कि जल्द ही जमानत दिलाकर जेल से बाहर निकालेंगे। पति के अलावा परिवार के अन्य लोग अनुष्का को पुलिस के पीछे-पीछे जेल तक छोड़ने पहुंचे। डीजीसी क्राइम दिलीप अवस्थी ने बताया कि अनुष्का तिवारी दांतों की डॉक्टर हैं। उन्होंने अपनी फील्ड से हटकर एक सर्जन के रूप में हेयर ट्रांसप्लांट किया। इस संबंध में एफआईआर दर्ज हुई थी। जांच में अनुष्का के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं।

9 मई को हुई थी एफआईआर

रावतपुर थाना पुलिस ने 9 मई को डॉ. अनुष्का तिवारी के खिलाफ इलाज में लापरवाही से मौत की एफआईआर दर्ज की थी। यह एफआईआर पनकी पावर हाउस ऑफिसर्स कॉलोनी में रहने वाली जया त्रिपाठी की शिकायत पर दर्ज हुई थी। जया ने आरोप लगाया था कि उनके पति इंजीनियर विनीत कुमार दुबे पनकी पावर हाउस में एक्सईएन थे। उन्होंने डॉ. अनुष्का के इंपायर क्लीनिक वाराही से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था।

बीजेपी सांसद को अपने से ही दिलवा रहे गाली, विपक्ष ठोक रहा ताली

» आरोपी चपरासी फरार, ब्लॉक प्रमुख के रिश्ते भी सवालों में

» 23 मिनट की वायरल ऑडियो में 27 बार गाली मचा सियासी बवाल

» फरार चपरासी की तलाश में पुलिस की कई टीमें

शुरुआती जांच में राहुल की आखिरी मोबाइल लोकेशन राजधानी लखनऊ में ट्रेस की गई, जिसके बाद कानपुर से दो पुलिस टीमें लखनऊ भेजी गईं।

वरिष्ठ संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर । कानपुर में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राहुल शुक्ला की एक आपत्तिजनक ऑडियो रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। इस ऑडियो में वह भाजपा के एक मौजूदा सांसद को बेहद अपमानजनक और अश्लील भाषा में गालियां देते हुए सुना गया है। मामला प्रकाश में आते ही प्रशासन सतर्क हुआ और पुलिस ने राहुल की तलाश शुरू कर दी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार राहुल शातिर किस्म का व्यक्ति है, जिसके ऊपर पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि वह क्षेत्र में लंबे समय से दबंगई और राजनीतिक रसूख के चलते चर्चा में रहा है। अब पुलिस उन संभावित ठिकानों की भी छानबीन कर रही है जहां से उसे भगाने या छिपाने में मदद मिली हो सकती है। प्रशासन ने यह संकेत दिए हैं कि इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

ब्लॉक प्रमुख के साथ बातचीत में कई बार सांसद का जिक्र

वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग में राहुल शुक्ला की बातचीत शिवराजपुर ब्लॉक प्रमुख शुभम बाजपेई से होती सुनाई दे रही है, जिसमें सांसद के अलावा कई अन्य संभ्रांत व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों का नाम लेकर बार-बार गंदी गालियों का प्रयोग किया गया है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है, क्योंकि वे राहुल की बातों का समर्थन करते हुए कई बार हां में हां मिलाते हैं, और एक जगह तो ठहाका लगाकर हंसते भी हैं। ऑडियो के अंत में वह चाय पर मिलने का न्योता भी देते हैं, जिससे उनकी निकटता और संलिप्तता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि शुभम बाजपेई ने दावा किया है कि यह ऑडियो उनके खिलाफ साजिश है और उन्होंने इस बातचीत को नकारते हुए इसे फर्जी बताया है। उनका कहना है कि उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है और वे जल्द ही इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराएंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि यदि ऑडियो असली निकला, तो ब्लॉक प्रमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

सस्पेंशन और केस दर्ज, मददगारों की भी तलाश

ऑडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए राहुल शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बीएसए ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा और आचरण किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए अस्वीकार्य है। साथ ही चौबेपुर थाना क्षेत्र के बोझा गांव निवासी नागेन्द्र सिंह ने शिवराजपुर पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि राहुल शुक्ला ने सिर्फ सांसद को नहीं, बल्कि पूरे क्षत्रिय समाज को अपमानित करते हुए गंभीर धमकियां दी हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें जान से मारने की धमकी और जातिगत अपमान की धाराएं शामिल की गई हैं। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि किन लोगों ने राहुल को फरार होने में मदद की। सूत्रों की मानें तो कुछ राजनीतिक और प्रभावशाली चेहरे पुलिस के राडार पर आ चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम से सियासी माहौल गर्म हो गया है और विपक्ष भी इस मामले को लेकर हमलावर हो सकता है। फिलहाल प्रशासन ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराने की तैयारी में है ताकि इसकी सत्यता की पुष्टि हो सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

» कानपुर के बिठूर रतन प्लैनेट अपार्टमेंट की घटना

पार्किंग विवाद में सोसाइटी सचिव की नाक चबा डाली

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। पार्किंग में खड़ी गाड़ी को हटवाने के विवाद में बिठूर के एक अपार्टमेंट की सोसाइटी के सचिव और फ्लैट मालिक के बीच विवाद हो गया। हाथापाई के दौरान फ्लैट मालिक ने दांत से सोसाइटी सचिव की नाक काट डाली। लहूलुहान हालत में परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रिटायर्ड इंजीनियर रूपेंद्र सिंह यादव नारामऊ स्थित रतन प्लैनेट अपार्टमेंट में रहते हैं। वह वहां की सोसाइटी के सचिव भी है। रूपेंद्र की बेटी प्रियंका ने बताया रविवार शाम पिता के पास अपार्टमेंट में रहने वाले क्षितिज मिश्रा का फोन आया। कहा कि उसकी पार्किंग में किसी और की गाड़ी पार्क है। पिता ने गार्ड भेजकर गाड़ी हटवाने की बात कही, लेकिन क्षितिज ने उन्हें नीचे बुलाया। आरोप है कि नीचे पहुंचते ही क्षितिज ने रूपेंद्र पर पहले थप्पड़ बरसाए, फिर अचानक उनकी नाक चबा डाली।

इससे वह लहूलुहान होकर पार्किंग में गिर पड़े। पूरी घटना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी होने पर पेशे से वैज्ञानिक बेटे प्रशांत व प्रियंका उन्हें एक निजी अस्पताल ले गए। प्रियंका के मुताबिक नाक के आगे का मांस अलग हो गया है। अब पिता को इलाज के लिए दिल्ली ले जाएंगे। वहीं, पुलिस ने बेटे प्रशांत की शिकायत पर ने क्षितिज मिश्रा के खिलाफ बिठूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर बिठूर प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने बताया कि पीड़ित का मेडिकल कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

बॉम्बे हॉस्पिटल
नियर आघू रोड, कानपुर-आगरा हाईवे, अकबरपुर, कानपुर देहात

24 घंटे इमरजेंसी सुविधा
24 घंटे एम्बुलेंस व मेडिकल स्टोर की सुविधा
दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन
हेल्पलाइन नं.: 8355017999, 8858997333

हड्डी के सभी ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी
पित्ताशय की पथरी, फिशर, नासूर
अपेन्डिक्स, प्रोस्टेट, कैंसर की गांठ, भगंदर
हर्निया, हाइड्रोसील, छाती का कैंसर
पेट की चोट व अन्य समस्याएं
बच्चेदानी व अण्डाशय की गांठ
घुटने का प्रत्यारोपण, पाइल्स (बवासीर)

डॉ. सुरेश यादव
डायरेक्टर

सम्पादकीय

सत्ता का अस्त्र बनने पर कोर्ट की फटकार

यह कोई नई बात नहीं है कि देश की जांच एजेंसियों पर सरकार की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से पक्षपात के आरोप लगे हों। सरकारी जांच एजेंसियों को वे विपक्ष के नेताओं को डराने-धमकाने का हथियार बताते रहे हैं। अब इन्हीं चिंताओं और सवालों पर देश की शीर्ष अदालत ने भी मोहर लगाई है। विपक्षी नेता खासकर धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाइयों पर रोक लगाने की गुहार लगाते रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय सरकार के हितों की पूर्ति के लिये दुराग्रह से कार्रवाई करता है। हालांकि, अदालत का मानना रहा है कि भ्रष्टाचार,देशविरोधी गतिविधियों तथा आतंकवादी संगठनों को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अतार्किक नहीं है।

सवाल इस बात को लेकर भी उठते रहे हैं जितने आरोप पत्र ईडी द्वारा दायर किए जाते हैं, उसकी तुलना में दोषसिद्धि की संख्या में बेहद ज्यादा अंतर क्यों है। जो इस बात की ओर इशारा करता है कि मामले दुराग्रह से प्रेरित होते हैं। अदालत भी मानती है कि ठोस प्रमाण के बिना किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक हालिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कारगुजारियों पर कोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाते हुए सीमाएं लांघकर संघीय ढांचे के अतिक्रमण करने की बात कही है।

कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु में शराब की दुकानों के लाइसेंस देने में बरती गई कथित धांधली में राज्य विपणन निगम के विरुद्ध धनशोधन मामले में ईडी की जांच पर की है।दरअसल, निगम द्वारा शीर्ष अदालत में मामला ले जाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जांच रोकी बल्कि ईडी की कारगुजारियों पर सख्त टिप्पणियां भी की हैं। निस्संदेह, ईडी को इस सुप्रीम नसीहत पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि प्रवर्तन निदेशालय संघीय अवधारणा का उल्लंघन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि पीएमएलए की धाराओं के दुरुपयोग को लेकर शीर्ष अदालत पहले भी ईडी के खिलाफ सख्त टिप्पणी कर चुकी है।

निस्संदेह, अदालत की इस सख्त टिप्पणी से उन तमाम विपक्षी दलों को संबल मिलेगा जो आए दिन ईडी व अन्य जांच एजेंसियों का सत्तापक्ष द्वारा दुरुपयोग करने का आरोप लगाते थे। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की दलील थी कि जिन शराब की दुकानों के लाइसेंस देने में अनियमितताओं के मामले में ईडी ने हस्तक्षेप किया है, उसमें वर्ष 2014 से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस मामले में चालीस से अधिक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं निगम कई मामलों में शिकायतकर्ता है। ऐसे में इस मामले में ईडी के कूदने पर सवाल उठे हैं।

यही वजह है कि कोर्ट ने ईडी की इस जांच पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार भी ईडी की कार्रवाई को संवैधानिक अधिकारों व संघीय ढांचे का उल्लंघन बताती रही है। विश्वास किया जाना चाहिए कि कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद ईडी केंद्र की इच्छाओं के अनुरूप आंख बंद कर कार्रवाई करने की बजाय अपनी कार्यशैली में अपेक्षित परिवर्तन करेगी।

राजनीतिक गरिमा और वक्त की नजाकत का सवाल

ज्योति मल्होत्रा

ऑपरेशन सिंदूर का औचित्य समझाने को सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनियाभर में भेजे जाने का फैसला लिया गया। ताकि सभी देशों तक संदेश पहुंचे कि पड़ोसी देश आतंकवाद को भारत के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर बिना पार्टी से अनुमति लिए हामी भर दी। उधर विदेश नीति पर सवाल उठे। राजनीति में गरिमा और अवसर का ख्याल जरूरी है।पहलगाम में हुए नरसंहार के जवाब में भारत को पाकिस्तान पर दंडात्मक सैन्य कार्रवाई क्यों करनी पड़ी, दुनिया को यह समझाने के लिए भेजे जाने वाले बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने को लेकर जो माहौल बना है, उसमें निश्चित तौर पर शालीनता की कमी देखी गई।

शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह ने इन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल होने के पीएम मोदी के आह्वान पर अपनी पार्टी, कांग्रेस से अलग होकर प्रतिक्रिया दी – कांग्रेस द्वारा सरकार को भेजी गई सूची में उनके नाम नहीं थे। इस पुरानी पार्टी को इस मुद्दे पर जिस प्रकार किरकिरी झेलनी पड़ गई। इसका पूर्वानुमान उसे होना चाहिए था।सोचा भी नहीं जा सकता कि राहुल गांधी की कांग्रेस वही कांग्रेस है, जिस पर कभी इंदिरा गांधी का राज रहा था। साल 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध करने से पहले के हफ्तों में, उन्होंने और उनके सबसे करीबी सहयोगियों ने कई महीनों तक कूटनीतिक अभियान चलाकर माहौल बनाया, ताकि पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में पैदा हुए मानवीय संकट को दुनिया के सामने रखा जा सके। साल 1994 की बात है, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और भारत को कश्मीर मुद्दे पर जेनेवा में मानवाधिकार परिषद में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था – तब राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करके पूछा कि क्या वे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत के संसदीय इतिहास में वह क्षण एक तरह से राजनीतिक किंवदंती के रूप में याद किया जाता है – 1994 में उप विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद, जो कोई भी उनसे मिलने आता, उसे यह बताने में कभी नहीं चूकते कि वाजपेयी के साथ काम करना कितना सहज है। साल 2018 में वाजपेयी के निधन के बाद खुर्शीद ने द प्रिंट नामक वेबसाइट को बताया - 'हमें एक-दूसरे को मनाने की या बहस करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। सहज रूप से हमारी सोच एक-सी थी और वे (वाजपेयी) बहुत कमाल के इंसान थेज्उनके पास वह 'मखमली स्पर्श' था, जो एक प्रेरक नेता होने के लिए चाहिए।'अब बहुत से लोग मोदी पर 'मखमली स्पर्श' विहीन होने का आरोप नहीं लगा सकते। निश्चित रूप से, मोदी का तरीका अपना संदेश सपाट रूप से संप्रेषित करने का है। होना तो यह चाहिए था कि मोदी फोन उठाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल करते और उनसे कहते - 'भाई, मैं सोच रहा हूं कि भारत को इस घड़ी एक स्वर में दुनिया को बताना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है; किस प्रकार हमारा यह पड़ोसी मुल्क कट्टरता और आतंकवाद का इस्तेमाल कर खेल कर रहा है; तिस पर यह धमकी कि कुछ करके देखो परमाणु हथियार चला दूंगा, एक ऐसा खतरनाक घालमेल जिसके सामने किम जोंग उन जैसा भी फीका पड़ जाए।'दुर्भाग्यवश, राष्ट्रहित में अहंकार और राजनीतिक मतभेद भुलाकर काम करने की क्षमता का प्रदर्शन करने वाला इस प्रकार का आह्वान इन दिनों संभव नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में शालीनता की कमी ही अब इसकी पहचान बन चुकी है। कोई भी पक्ष दूसरे का सम्मान नहीं करता। पीएम मोदी का मानना है कि राहुल लोगों से कटे हुए वंशवादी नेता हैं, जिसे सीखने से परहेज है और बदतर यह कि पार्टी उन्हें हटा भी नहीं सकती, भले ही उनके नेतृत्व तले कांग्रेस चुनाव-दर -चुनाव हारती जा रही हो। उधर राहुल का मानना है कि पीएम मोदी लोकतांत्रिक संस्थाओं के सबसे बड़े विध्वंसक हैं।

सार्वजनिक मंचों से दोनों एक-दूसरे की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब वे एक-दूसरे से भिड़ नहीं रहे होते, तब उनके करीबी सहयोगी यह कमी पूरी करते हैं। देश के दो शीर्ष नेताओं के बीच ताने, कटाक्ष, सरासर बेइज्जती करना है।

जड़ों से उखड़े लोगों को फिर से बसाने की चुनौती

विस्थापन की त्रासदी

सुरेश सेठ

पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम आतंकी की विधवाओं और आतंकवाद से लड़ते शहीद हुए जवानों की विधवाओं का दर्द कम करने और अनाथ हुए बच्चों को संबल देने की कोशिश की। सत्ता से जुड़ी आवाजें दावा करती हैं कि प्रतिकार हो गया, आततायियों को सबक सिखा दिया गया। लेकिन उन लोगों के दर्द का क्या, जो सरहद के गांवों से विस्थापित होकर अपने घर-बार समेट कर अनजाने ठिकानों की ओर चल पड़े?पंजाब की सीमाओं पर तो ऐसे खेत भी हैं जो आधे हिस्से में सरहद के पार चले जाते हैं। कहीं फसलें समय से पहले काट ली गईं, और जहां नहीं काटी जा सकीं, वहां न केवल फसलें तबाह हुईं, जिससे किसानों की मेहनत भी मिट्टी में मिल गई। उखड़ना और फिर से बसना-शायद यही इन लोगों की नियति बन गई है।

युद्धविराम के बाद कुछ सरहदी गांवों के लोग जब लौटे, तो उन्हें तबाही का मंजर देखना पड़ा। इस हिंसा के साथ एक और डरावना पहलू भी जुड़ा था—आतंकी और माफिया गिरोहों की हिंसा, जिन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी गैर-कानूनी गतिविधियों का जाल फैला रखा है। ये लोग दिनदहाड़े लूटमार करते हैं और लोगों को उनके अपने घरों में ही पराया बना देते हैं। बाढ़, तूफान और हिंसक घटनाएं आम लोगों के जीवन का कटु सत्य बन चुकी हैं। कुल मिलाकर, जो लोग दुर्भाग्यवश अपनी जड़ों से उखड़ गए हैं, उनकी संख्या लाखों तक पहुंच चुकी है। ये विस्थापन न केवल युद्ध और आतंकवाद के कारण हुआ, बल्कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और

भूमि-क्षरण जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी इस त्रासदी को बढ़ाया।किसान सिर्फ शांति का इंतजार नहीं करता; वह अपनी फसल के लिए समय पर पानी और कटाई के समय साफ मौसम की आशा करता है। लेकिन हालात उलटे हो गए—जहां शांति चाहिए थी, वहां हिंसा मिली; जब पानी की जरूरत थी, तब सूखा पड़ा, और मौसम साफ के समय इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि बादल फटने लगे। उधर मणिपुर में भी एक छद्म युद्ध आतंकियों द्वारा जातिगत आरक्षण के मुद्दे को लेकर लड़ा जा रहा है। आगजनी और हिंसा के चलते वर्ष 2024 में मणिपुर से हजारों लोग विस्थापित हुए।

जिनेवा स्थित मॉनिटरिंग सेंटर के अनुसार, केवल असम में ही पिछले एक दशक में आई भीषण बाढ़ों के कारण 25 लाख लोग आंतरिक विस्थापन का शिकार हुए हैं। इसी तरह, देशभर में आए भीषण चक्रवातों ने 16 लाख से अधिक लोगों को उजाड़ दिया। बंगाल की खाड़ी में अक्तूबर 2024 के अंत में आए चक्रवात 'दाना' ने 10 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया। त्रिपुरा का भी यही हाल रहा है। पिछले 40 वर्षों में प्रतिकूल मौसम की वजह से वहां 3.15 लाख लोग अपने घरों से उजड़ चुके हैं।

पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात 'रेमल' ने 2 लाख 8 हजार लोगों को उनके घर-द्वार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के उफान के कारण लगभग 3 लाख 38 हजार लोग विस्थापित हुए हैं। निस्संदेह, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, लेकिन इस कार्रवाई से सीमा पर बसे लोगों से लेकर दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक की जिंदगियां अव्यवस्थित हो गईं। लोग फिर से अपनी जड़ों से उखड़ने को मजबूर हो गए। जंग, आखिर जंग होती है। क्या उनके वे सपने, जो बारूद की गंध में घुलकर टूट गए या बिखर गए, दोबारा संवर पाएंगे? जिन नौजवानों की आंखों से भविष्य की चमक धुंधला गई है, उसका समाधान कैसे होगा? स्पष्ट है कि न युद्ध से, न प्रदूषणजनित अव्यवस्था से और न ही प्राकृतिक आपदाओं से मानवीय संकट को दूर करने के गंभीर प्रयास हो रहे हैं। इस दिशा में सत्ता की संवेदनशीलता अपरिहार्य है।इस संसार के नीति-नियंताओं को यह सोचना होगा कि आम लोगों की ज़िंदगी में फिर से सपनों में रंग कैसे भरे जाएं। उन युवाओं के लिए उम्मीद की कोई बुनियाद रखनी होगी, जो गांवों से शहर और शहरों से फिर गांव लौटने को मजबूर हैं।

अनुपम खेर ने पूरे किए बॉलीवुड इंडस्ट्री में 41 साल

अभिनेता ने बताया अपना फिल्मी करियर

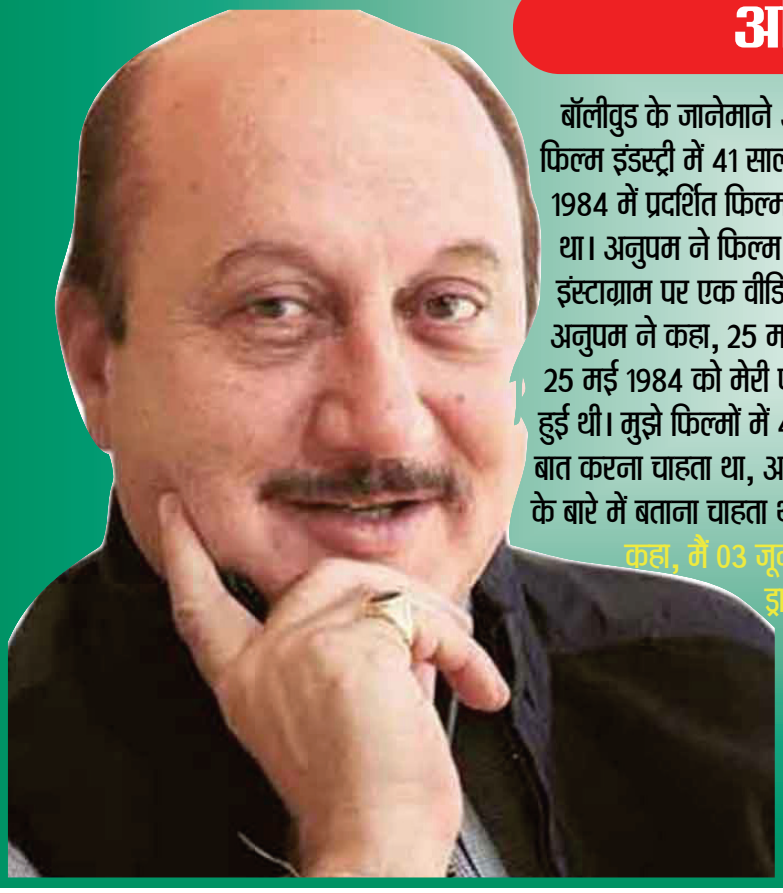

बॉलीवुड के जानेमाने अभिनेता-फिल्मकार अनुपम खेर ने फिल्म इंडस्ट्री में 41 साल पूरे कर लिये हैं। अनुपम खेर ने वर्ष 1984 में प्रदर्शित फिल्म 'सारांश' से फिल्मों में डेब्यू किया था। अनुपम ने फिल्म इंडस्ट्री में 41 साल पूरे होने पर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में अनुपम ने कहा, 25 मई 2025 से 41 साल पहले यानी 25 मई 1984 को मेरी पहली फिल्म 'सारांश' रिलीज हुई थी। मुझे फिल्मों में 41 साल हो गए हैं। मैं आपसे बात करना चाहता था, आपको अपने 41 साल के सफर के बारे में बताना चाहता था। अनुपम ने वीडियो में आगे कहा, मैं 03 जून 1981 को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलकर मुंबई आया था। उसके बाद मैं लखनऊ में पढ़ाता रहा। फिर मैंने तीन साल तक काम की तलाश की और फिर मिस्टर भट्ट ने मुझे सारांश दी। अब 41 साल हो गए- पलकें झपकते गुजर गए। सारांश के 41 साल। यह कितना खूबसूरत सफर रहा है। कितना आभारी सफर रहा है। मेरे सफर में उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन यह बहुत अच्छा रहा है।मैंने कम से कम 544 या 545 फिल्में की हैं। आज मैं सोच रहा था कि इन 41 सालों में मेरे जीवन में क्या बदलाव आया है। अनुपम खेर इन दिनों फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को लेकर चर्चा में हैं। अनुपम खेर ने इस फिल्म का निर्देशन खुद किया है। हाल ही में इस फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। जहां इसे काफी सराहना मिली थी। यह फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

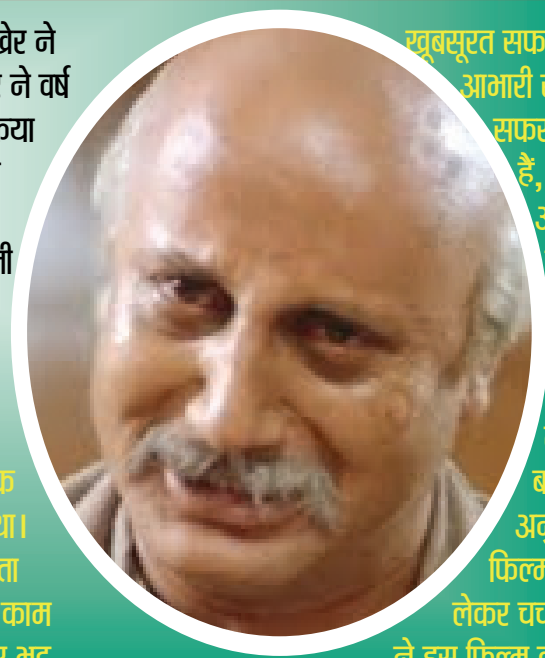

मैं टुच्ची चीज में नहीं पड़ता चुनरी चुनरी गाने के रीमेक पर बोले अभिजीत भट्टाचार्य

चुनरी चुनरी गाने को वरुण धवन की आगामी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में इस्तेमाल किया जाएगा। गाने के रीमेक पर इस गाने के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया दी है।पुराने गानों को रिक्रिएट करने का चलन जोरों पर है। अब वरुण धवन की आगामी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में फिल्म बीवी नंबर 1 के चर्चित गाने चुनरी चुनरी को रिक्रिएट किया जाएगा। मूल रूप से इस गाने को अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया। हाल ही में जब उनसे इस गाने के रीमेक को लेकर पूछा गया तो सिंगर ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता।

फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। हाल ही में अभिजीत से इस फिल्म में चुनरी चुनरी गाने के रीमेक को लेकर पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि म्यूजिक कंपोजर और निर्देशक (डेविड धवन) ने उन्हें गाने के रीमेक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अभिजीत ने कहा, हिम्मत भी नहीं कर सकते बताने की। सिंगर ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में यह खुलासा किया।

ऑरिजनल की कीमत सब नहीं जानत

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें गाने के नए वर्जन से कोई परेशानी है? इस पर अभिजीत ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता इतनी छोटी चीजों से। मैं इसमें ज्यादा शामिल नहीं होता। बाजार में कॉपी की बिक्री मूल से ज्यादा होती है। सिर्फ महान लोग ही ऑरिजनल की कीमत जानते हैं। टुच्ची चीजों में मैं पड़ता ही नहीं हूं। बोले- यह गाना कभी पसंदीदा नहीं रहाइसके अलावा सिंगर ने कहा कि यह गाना कभी उनका पसंदीदा नहीं रहा। उनके अनुसार चुनरी चुनरीएक बेहतरीन गाना नहीं था, बल्कि इसे बहुत जल्दबाजी में गाया गया था। यह उनके शानदार गानों की लिस्ट में रहा ही नहीं। हालांकि, अभिजीत ने यह बात मानी की फैंस के बीच यह एक आइकॉनिक गाना बन गया।

सीएम योगी को भेंट किया गोवंश संरक्षण पर मिला सर्टिफिकेट

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नगर निगम कानपुर के द्वारा किशनपुर में संचालित कान्हा गौशाला को प्रदेश स्तर पर पहचान मिल रही है। यहां पर संरक्षित गोवंशों को उच्च कोटि की सुविधा और खान-पान का इंतजाम किया जा रहा है।

इस पर आइएससो 9001—2015 संस्था के द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कानपुर नगर निगम के नगरआयुक्त सुधीर कुमार द्वारा कानपुर नगर निगम द्वारा कान्हा गौशाला के सर्वोच्च संचालन किए जाने हेतु मिले द्वुस्ह 9001-2015 प्रमाण पत्र को भेट किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के कार्यो को सराहा। वही आपको बता दें कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरके निरंजन के द्वारा लगातार पर्यवेक्षण और देखरेख की वजह से नगर निगम ने अपना डंका बजाया है।

नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने लखनऊ पहुंचकर भेंट किया ISO 9001-2015 का प्रमाण पत्र

स्वराज इंडिया www.swarajindianews.com कानपुर सिटी कानपुर, शुक्रवार 09 मई, 2025 07

प्रदेश के लिए नजीर
किशनपुर की कान्हा गौशाला

» नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने किया निरीक्षण
» गोवंशों के लिए किए गए इंतजाम देख कर सन्तोष व्यक्त किया गया

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। मुख्यमंत्री योगी की परिकल्पना के अनुरूप नगर निकाय क्षेत्रों में स्थापित गौशालाओं में संरक्षित गोवंश के नियमित संरक्षण तथा व्यापक खाद्यान व चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं के नियमित पर्यवेक्षण के निर्देश है । कानपुर की किशनपुर कान्हा गौशाला प्रदेश के लिए नजीर पेश कर रही है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार द्वारा कान्हा गौशाला, किशनपुर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। सीवीओ डॉक्टर आरके निरंजन ने बताया किकान्हा गौशाला में कुल 5259 गौवंश (1251 नर गौवंश एवं 4008 मादा गौवंश) को संरक्षित किया गया है। वहीं गौशाला में निर्मित समस्त शेडो की चरहियो में पर्याप्त मात्रा में भूसा, चोकर एवं हराचारा पाया गया। गौशाला में संरक्षित गौवंशो को पीने का उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्मित नादो में साफ-सफाई के साथ-साथ स्वच्छ जल भी पाया गया। गौशाला में पानी की आपूर्ति हेतु एक विशाल ओवर हैड टैंक उपलब्ध है।

कान्हा गौशाला में स्थित 02 भूसा भण्डारण कक्ष में लगभग 2000.00 कु0 भूसा एवं 100.00 कु0 चोकर उपलब्ध पाया गया, जिस पर नगर आयुक्त के द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। गौशाला में संरक्षित गौवंश को प्रतिदिन हराचारा उपलब्ध कराने हेतु 200.00 – 300.00 कु0 हराचारा की आपूर्ति होती है, जो कि तद्दिनांक ही गौवंशो को खिलाया जाता है।

आगामी माह में सम्भावित भीषण गर्मी पड़ने पर गौवंश के बचाव हेतु शेडो में पंखे तथा मिस्ट की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया है। कान्हा गौशाला में संरक्षित गौवंशो से उत्पादित गोबर का शत-प्रतिशत उपयोग कर वर्मीकम्पोस्ट, गोबर-गैस प्लांट तथा अन्य उत्पाद जैसे गोबर पेंट का उत्पादन करने के निर्देश दिये गये। नगर आयुक्त को अवगत कराया गया कि एक दर्जन से अधिक ग्रामीण महिलाओं द्वारा उपलो का निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्रति माह रू0 40,000.00 की आय नगर निगम को हो रही है, साथ ही साथ वर्मी कम्पोस्ट का भी निर्माण कराया जा रहा है।

वर्तमान में नेपियर घास का उत्पादन कान्हा गौशाला में किया जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल 01 एकड़ है। नगर आयुक्त के द्वारा नेपियर का क्षेत्रफल बढ़ाकर 01 से 10 एकड़ करने के निर्देश दिये गये है।

गौशाला के बाहर पानी का जमाव पाये जाने पर उनके द्वारा इंजीनियरिंग विभाग को पानी की निकासी के लिये प्रस्ताव बनाकर प्रेषित किये जाने हेतु आदेशित किया गया।

नगर आयुक्त द्वारा नव निर्मित राधिका उपवन में गौवंश की संख्या कम पाये जाने पर यह निर्देश दिये गये कि यहाँ पर नगरीय क्षेत्र से पकड़कर 1000 गौवंश लाये जाये और उनको संरक्षित किया जाये। नगर आयुक्त के द्वारा कान्हा गौशाला परिसर में स्थित वेटनरी हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर का निरीक्षण किया गया। ट्रामा सेंटर में रखकर 08 गौवंश की समुचित चिकित्सा की जा रही है। वहाँ पर उपस्थित पशुचिकित्सा अधिकारी डा0 हरिकान्त के द्वारा यह अवगत कराया गया कि वह स्वयं प्रतिदिन गौवंश की चिकित्सा का कार्य देखते है, साथ ही साथ 24 घण्टे के लिये पैराबेट की नियुक्ति भी की गयी है। मौके पर सीवीओ डा0 आर0के0 निरंजन के साथ डा0 शिल्पा सिंह, पशुचिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी, डा0 हरिकान्त, पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, श्री दिनेश कुमार, राजस्व निरीक्षक, श्री ऋषीकेश, गौशाला प्रभारी एवं अन्य कर्मी उपस्थित रहें।

एबीसी सेंटर का भी किया निरीक्षण

किशनपुर स्थित नवीन ए0बी0सी0 सेन्टर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। ए0बी0सी0 सेन्टर 20 दिन पूर्व प्रारम्भ किया गया है। मौके पर एक ही वेटरिनरी सर्जन के द्वारा सर्जरी की जा रही है, जिससे प्रतिदिन लगभग 20 सर्जरी हो पाती है। नगर आयुक्त के द्वारा निर्देशित किया गया कि ए0बी0सी0 सेन्टर को उसकी पूर्ण क्षमता से संचालित कर प्रतिदिन 40 कुत्तो की नसबन्दी की जाये। ए0बी0सी0 सेन्टर और कान्हा गौशाला के मध्य गेट का निर्माण कराया जाये। मौके पर उपस्थित वेटनरी सर्जन डा0 प्रदीप दीक्षित के द्वारा यह अवगत कराया गया कि नगरीय क्षेत्रो से आवारा कुत्तो को पकड़कर ए0बी0सी0 सेन्टर पर नसबन्दी कार्य हेतु लाया जाता है तथा पकड़ने जाने के अगले दिन उनकी सर्जरी की जाती है तत्पश्चात् दो दिन की पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर तथा एन्टी रेबीज टीका लगाने पश्चात कुत्तो को उनके मूल स्थान पर ही छोड़ दिया जाता है। नगर आयुक्त महोदय के द्वारा सम्पूर्ण नसबन्दी की कार्यवाही, ए0बी0सी0 रूल्स 2023 के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये ।

बीमार पशुओं के उपचार प्रबन्धन को सराहा

नगर आयुक्त के द्वारा नगरीय क्षेत्र से लाये जा रहे दुर्घटनाग्रस्त/बीमार/अशक्त/ घायल/वृद्व गौवंश की जा रही चिकित्सा कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी और नगर निगम द्वारा दी जा रही वेटनरी एम्बुलेंस की सुविधा को और बेहतर करने तथा ट्रामा सेन्टर में बीमार गौवंश को लाकर गहन चिकित्सा के निर्देश भी दिये गये। सम्पूर्ण गौशाला एवं वेटनरी हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर की निरीक्षण के उपरान्त उपलब्ध व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्राइवेट कंपनी द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटरों की केस्को कराएगा जांच

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। शहर में स्मार्ट मीटर इसलिए लगाए गए, ताकि बिजली की चोरी न हो सके और लोग समय पर बिल का भुगतान कर सकेंगे, लेकिन शहर के कुछ लोग ने इसका भी तोड़ निकल लिया है। बिजली बिल का भुगतान करने से बचने के लिए फर्जी स्मार्ट मीटर ही घर में लगा लिया। इसकी जानकारी तब हुई, जब केस्को की विजिलेंस विभाग की टीम ने छापा मारकर पकड़ा, इस मामले के केस्को अलर्ट हो गया है और स्मार्ट मीटरों की जांच शुरू कराने का फैसला लिया है। कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी के अंतर्गत शहर में करीब एक लाख 52 हजार लोग स्मार्ट मीटर धारक है। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जीनस कंपनी को मिला था, इसके अलावा एक अन्य कंपनी ने भी शहर के मुख्य जगहों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया था। वहीं, वर्तमान में चमनगंज क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के संबंध में केस्को व विजिलेंस टीम मिलकर बिजली चोरी रोको अभियान का संचालन सुबह से लेकर रात तक हर रोज कर रही है। इस अभियान में केस्को की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। केस्को टीम ने दो घरों में फर्जी स्मार्ट मीटर पकड़े है, इसके बाद से केस्को टीम और अलर्ट हो गई है।

सार्वजनिक नोटिस

थाना बिल्हौर पर पंजीकृत मु0अ0स0 134/2024 धारा 394 भादवि0 मे वांछित अभियुक्त दिलीप उर्फ खलीफा पुत्र सीताराम निवासी भगतसिंह नगर थाना बिल्हौर कानपुर नगर के विरूद्व माननीय न्यायालय के आदेश अन्तर्गत धारा 82 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही कर डुगडुगी बजवाई गई व लाउड स्पीकर से मुनादी की कार्रवाई की गई। अन्तर्गत धारा 82 सी0आर0पी0सी0 की नोटिस की प्रति अभियुक्त के घर के दरवाजे पर चस्पा की गई तथा दिखायी देने वाले स्थानों पर व आसपास के अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चस्पा की गई।

आज्ञा से कोतवाली प्रभारी बिल्हौर, कानपुर नगर।

चालक को आई झपकी, आपस में टकराई स्लीपर, दर्जन घायल

- तीन घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही
- अरौल थाना क्षेत्र से गुजरे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा हादसा
- दिल्ली से गोंडा जा रही स्लीपर बस हुई दुर्घटना का शिकार
- मुख्यमंत्री ने हादसे को लिया संज्ञान में

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर। सोमवार तड़के अरौल थाना क्षेत्र से गुजरे आगरा लखनऊ-एक्सप्रेस वे पर मकनपुर गांव के समीप हादसा हो गया। आगे चल रही दिल्ली से गोंडा जा रही स्लीपर बस संख्या यूपी 81 सीपी 3034 में पीछे से आ रही बस संख्या यूपी 55 एटी 9670 के चालक को नींद की झपकी आ जाने पर जोरदार टक्कर मार दी। जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आगे चल रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में दोनों बसों पर सवार करीब 30 लोग घायल हो गए। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची अरौल पुलिस ने बस से रेस्क्यू कर सभी घायल यात्रियों को एम्बुलेंस की मदद से बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 26 यात्रियों को कानपुर रेफर कर दिया। जिसमे से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में अरौल इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है। घटना के बाद से दोनों बसों के चालक परिचालक फरार हैं। प्रथम दृष्टया नींद की झपकी आने से दुर्घटना होना प्रतीत हो रहा है।

सीएम योगी ने लिया तत्काल संज्ञान में

बिल्हौर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे का सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए कानपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायल यात्रियों के समुचित उपचार के लिए निर्देशित किया।साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

वार्ड 64 में तिरंगे के साथ देशभक्ति का दिखा जोश

पार्षद नीरज बाजपेई ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के समर्थन में निकाली तिरंगा यात्रा, गूंजे देशभक्ति नारे

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। देश की रक्षा में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे भारत में जहां जनभावनाएं उफान पर हैं, वहीं कानपुर के वार्ड 64 सर्वोदय नगर में भी इसका समर्थन गूंज उठा। स्थानीय पार्षद नीरज बाजपेई के नेतृत्व में सोमवार को एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया।

यह यात्रा जेके मंदिर पुलिस चौकी लोहारन भट्ठा से प्रारंभ होकर वार्ड के प्रमुख मार्गों से होती हुई सम्पन्न हुई। तिरंगा लिए सैकड़ों की संख्या में युवाओं, बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने पूरे जोश और उल्लास के साथ यात्रा में भाग लिया।

रास्ते भर भारत माता की जय, जय हिन्द, और वंदे मातरम जैसे नारों से वातावरण गूंजता रहा।पार्षद नीरज बाजपेई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे सैनिकों के अद्वितीय साहस और बलिदान का प्रतीक है। यह तिरंगा यात्रा न केवल उनके सम्मान में है बल्कि आम जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना को सशक्त करने का एक प्रयास भी है। यात्रा के दौरान उन्होंने युवाओं से देश सेवा और समाजहित में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की।इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने भी तिरंगे के साथ पूरे उत्साह से हिस्सा लिया और वार्ड स्तर पर पहली बार इतने बड़े स्तर पर हुए आयोजन की सराहना की।

एक सप्ताह और बंद रहेगा चिड़ियाघर, चार शेरों के और भेजे सैंपल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। दो सप्ताह पहले राष्ट्रीय उच्च पशु रोग संस्थान भोपाल भेजे गए चिड़ियाघर वन्यजीवों के सैंपल की रिपोर्ट न आने पर चिड़ियाघर प्रशासन ने चिड़ियाघर को एक सप्ताह और बंद रखने का निर्णय लिया है। चार बब्बर शेरों के भोजन कम होने के कारण संक्रमण के शक पर उनका सैंपल लेकर जांच को भोपाल भेजा गया। वहीं, पशुपालन विभाग द्वारा पोल्ट्री फार्म से लिए गए 428 मुर्गा-मुर्गियों के सैंपल में से 292 की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

गोरखपुर चिड़ियाघर से कानपुर लाए गए बब्बर शेर पटौदी और मोर की बर्ड फ्लू से मौत के बाद से चिड़ियाघर में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। चिड़ियाघर में ब्राह्मी बतख की मौत होने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। बतख के साथ दो बाघिन और अन्य पक्षियों के सैंपल जांच के लिए राष्ट्रीय उच्च पशु रोग संस्थान भोपाल भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट नहीं आई है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम भी मिट्टी व पानी के नमूने जांच के लिए ले गई है।

सार्वजनिक सूचना

मैंने अपनी पुत्री का नाम छवि राजपूत से बदलकर श्रेया राजपूत कर लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। अभिलेखों में भी यही मान्यता दी जाए।

वीरेन्द्र कुमार पुत्र-श्री मंगली प्रसाद निवासी म0नं0-19, सरायमीता, पनकी, पंकज बहादुर नगर, पनकी गंगागंज, कानपुर। नगर-208020, उ0प्र0

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादक: अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

शिवली सीएचसी बना मनमानी और अराजकता का अड्डा

» शिवली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव केंद्र के बाहर गंदगी का साम्राज्य, ठप पड़ा वाटर कूलर मरीजों की परेशानी बढ़ा रहा

शिवांक अग्निहोत्री स्वराज इंडिया

शिवांक अग्निहोत्री, स्वराज इंडिया

कानपुर देहात। शिवली कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत इतनी बदतर है कि वह स्वयं में एक जांच का विषय बन चुका है। जब दैनिक स्वराज इंडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, तो जो दृश्य सामने आया वह स्वच्छ भारत अभियान के तमाम दावों और वादों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी था। खासकर अस्पताल के भीतर स्थित प्रसव केंद्र के बाहर की दीवारें और फर्श गुटखा, तंबाकू और पान की पीक से बुरी तरह रंगी हुई थीं, मानो यह अस्पताल नहीं बल्कि किसी सार्वजनिक शौचालय के पीछे की दीवार हो। इस दृश्य ने यह साफ कर दिया कि यहां स्वास्थ्य सुरक्षा की नहीं, बल्कि लापरवाही और गंदगी की नीतियां लागू हैं।

स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता की शर्मनाक तस्वीर

जन्म देने वाली माताएं और नवजात शिशु, जिनके लिए साफ-सुथरा वातावरण आवश्यक होता है, वे इसी गंदगी के बीच इलाज करवाने को मजबूर हैं। अस्पताल परिसर में न कहीं डस्टबिन नजर आया, न ही किसी साफ-सफाई कर्मी की उपस्थिति। मरीजों और परिजनों से बातचीत में सामने आया कि कई बार शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस गंभीर स्थिति को अस्पताल स्टाफ अब सामान्य मान चुका है। यह स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान की जमीनी सच्चाई को उजागर करती है, जहां अभियान का नाम केवल पोस्टर, स्लोगन और दीवार लेखन तक सीमित रह गया है, जबकि हकीकत बदबू, गंदगी और प्रशासनिक उदासीनता में सिसक रही है।

पानी की एक बूंद को तरसे मरीज

गर्मी अपने चरम पर है और ऐसे में ठंडे और स्वच्छ पानी की जरूरत हर इंसान की प्राथमिक आवश्यकता बन जाती है। लेकिन शिवली के इस स्वास्थ्य केंद्र में लगा वाटर कूलर महीनों से खराब पड़ा है और उसे लेकर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने मरीजों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है। न तो कूलर की मरम्मत के कोई संकेत दिखाई दिए, और न ही इसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई। मरीजों को मजबूर होकर इधर-उधर से पानी लाना पड़ता है या फिर पैसे खर्च कर बोतल खरीदनी पड़ती है। यह समस्या खासतौर पर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि उन्हें नियमित अंतराल पर साफ पानी न मिलना स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम बन सकता है।

टीम द्वारा जब इस संबंध में अस्पताल स्टाफ से सवाल किए गए, तो जवाब आया

मरम्मत की अर्जी डाली है, लेकिन ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं हुई।卐 यह कथन अपने आप में सिस्टम की सुस्ती और संवेदनहीनता का प्रमाण है। केंद्र सरकार एक ओर आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर पीने के पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता तक पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ये योजनाएं केवल कागजों और घोषणाओं तक सीमित हैं? जब सरकारी अस्पतालों में भी आम आदमी की जरूरतें नहीं पूरी हो पा रहीं, तो फिर सरकारी प्रयासों पर विश्वास करना जनता के लिए कैसे संभव होगा?

डेरापुर की गौशाला बनी यातनागृह

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। डेरापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत हारा मऊ की गौशाला में अफसरों की लापरवाही और पंचायत सचिव की मनमानी से एक बार फिर गौसेवा की सच्चाई सामने आ गई। डीएम आलोक सिंह और सीडीओ लक्ष्मी एन- ने हाल ही में अधिकारियों संग बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी गौशालाओं में छाया, पानी और हरे चारे की समुचित व्यवस्था की जाए। लेकिन इन निर्देशों को कागजों तक सीमित रखते हुए ज़मीनी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया गया।

» सत्ता में गौ माता की बात, ज़मीन पर तड़पती हकीकत—दो गोवंश की मौत, अफसरों की चुप्पी

नतीजा ये रहा कि रविवार को इस गौशाला में दो गोवंश की दर्दनाक मौत हो गई और उनका शव खुले में पड़ा रहा, जिसे आवारा कुत्ते नोचते रहे। गर्म हवाओं और सूखे भूसे से बेहाल गोवंश की हालत देखकर साफ है कि यहां कोई भी स्थायी व्यवस्था नहीं है।

तस्वीर वायरल, अफसर बेखबर मीडिया से बचाव की कोशिश

स्वराज इंडिया के कैमरे में कैद हुई हारा मऊ गौशाला की यह भयावह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। गौशाला में तैनात केयरटेकर, ग्राम प्रधान, सचिव से लेकर ब्लॉक स्तर के अधिकारी तक पूरी तरह नदारद दिखे। मृत गायों को तक दफनाने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जिससे मानवता को शर्मसार करती तस्वीरें सामने आईं। मीडिया की कवरेज से बौखलाए प्रशासन ने अब गौशाला में मीडिया के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है, जिससे सच्चाई बाहर न आ सके। सीडीओ ने जरूर बयान देते हुए कहा है कि प्रधान और सचिव के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, लेकिन यह सवाल बरकरार है कि क्या इससे व्यवस्था सुधरेगी या फिर गौशालाओं में यूं ही गोवंश दम तोड़ते रहेंगे?

जल्द ही कम विद्यार्थियों वाले विद्यालयों का होगा अन्य में विलय

शुरुआत में 10 या उससे कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का आपस में विलय किया जा सकता है

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों का विलय होगा। जिले में ऐसे सैकड़ों परिषदीय स्कूल हैं। शुरुआत में 10 या उससे कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का आपस में विलय किया जा सकता है। इस संबंध में विभागीय शिक्षक 15 जून के बाद अभिभावकों और प्रधानों की राय लेंगे। जिले में कुल 1925 परिषदीय विद्यालय हैं। इसमें करीब एक लाख तीस हजार से अधिक छात्र पंजीकृत हैं। राज्य परियोजना कार्यालय ने यू-डायस पोर्टल पर अंकित छात्र संख्या को आधार बनाते हुए नामांकन की प्रगति की समीक्षा की है। जनपद में कई ऐसे स्कूल हैं जहां विद्यार्थी दस से भी कम हैं और शिक्षक दो या उससे ज्यादा तैनात हैं।

वहीं कई विद्यालय ऐसे भी हैं, जहां पर पर्याप्त छात्र संख्या है और विभागीय मानक अनुसार शिक्षकों की तैनाती नहीं है। ऐसे में कम छात्रों वाले स्कूलों का विलय किया जा सकता है। इसको लेकर विभागीय शीर्ष अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी चरणवार तरीके से विद्यालयों का विलय करने पर चर्चा हुई है। बीएसए ने बताया कि स्कूलों में निर्धारित मानक के अनुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक, 60 बच्चों पर दो शिक्षक, 90 बच्चों पर तीन शिक्षक, 120 पर चार शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। देखा जाए तो यह मानक जिले के अधिकांश स्कूलों में पूर्ण नहीं है। कहीं अधिक शिक्षक तैनात हैं तो कहीं कम। बंद होने वाले स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को पास के स्कूलों में समायोजित करने की तैयारी शासन स्तर से शुरू कर दी गई है। साथ ही शिक्षकों का विषयवार ब्योरा भी जुटाया जा रहा है।

अभिभावकों से ली जाएगी राय

कम छात्रांकन वाले विद्यालयों का नजदीकी स्कूल में विलय किया जा सकता है हालांकि इससे पहले 15 जून के बाद अभिभावकों की

सहमति और प्रधानों से भी चर्चा की जाएगी ताकि किसी भी तरह की विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को कोई परेशानी न हो। इससे विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा। हर विषय का शिक्षक पढ़ाने के लिए उपलब्ध रहेगा। वहीं छोटे स्कूलों (आंगनबाड़ी केंद्रों) को प्री-प्राइमरीज के रूप में विकसित किया जा सकता है।

विद्यालय विलय नीति के दुष्प्रभाव

यदि 100 विद्यालयों का समायोजन हुआ तो वर्तमान मे प्रभावी व्यवस्था के अनुसार 100 प्रधानाध्यापक, 200 सहायक अध्यापक, 200 शिक्षामित्र, 100 रसोइया के पद समाप्त हो जायेंगे शिक्षक सरप्लस हो जायेंगे अर्थात नई भर्ती नही आयेगी। शिक्षामित्र विचाराधीन हो जायेंगे, रसोइयों की सेवा समाप्त हो जाएगी। छोटे बच्चों को स्कूल पहुंचने में परेशानी होगी, प्राइवेट स्कूलों की सक्रियता बढ़ेगी। निजी विद्यालयों को लाभ होगा क्योंकि उनके पास छोटे बच्चों के ढोने के साधन उपलब्ध हैं, साथ ही छोटे बच्चों के भाई बहन भी एक साथ रहने के लिए उसी स्कूल में दाखिला लेंगे।

यूपी सरकार का एलान: सामूहिक विवाह योजना में अब कन्याओं को सिंदूर भी किया जाएगा दान

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। पाकिस्तान पर सेना द्वारा किए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी सरकार ने बड़ा एलान किया है। अब प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना में कन्याओं को सरकार की तरफ से सिंदूरदान भी दिया जाएगा। इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। अब सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले उपहारों में कन्या को सिंधौरा (सिंदूरदान) भी दिया जाएगा।

इतना ही नहीं लाभ लेने के लिए कन्या पक्ष की अधिकतम आय

सीमा भी दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है।

प्रति जोड़ा खर्च 51 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने का शासनादेश भी जारी किया गया है।

शासनादेश के अनुसार, कन्या के अभिभावक का यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। विवाह योग्य आयु की पुष्टि के लिए स्कूल का रिकॉर्ड, जन्म प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड मान्य होंगे।

योजना में निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग बेटी को प्राथमिकता दी जाएगी।

खर्च में पुजारी-मौलवी की दक्षिणा व पारिश्रमिक भी शामिल ः जिलास्तर पर डीएम की निगरानी में समाज कल्याण अधिकारी सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराएंगे।

कन्या के खाते में 60 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। 25 हजार रुपये मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री दी जाएगी। प्रति जोड़ा 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च होगा।

विवाह समारोह के लिए जर्मन हैंगर की व्यवस्था की जाएगी

इस राशि में विवाह संपन्न कराने वाले पुजारी और मौलवी की दक्षिणा व पारिश्रमिक भी शामिल होगा।

100 या उससे अधिक जोड़ों के विवाह समारोह के लिए जर्मन हैंगर की व्यवस्था की जाएगी। यह पंडाल काफी उम्दा किस्म का होता है।

बाराबंकी: दोस्तों को जमकर शराब पिलाई.. उन्हीं ने छत से फेंक दिया

» हमले में मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है छोड़ें या फिर रेंज

स्वराज इंडिया संवाददाता

बाराबंकी। शहर के आवास विकास क्षेत्र स्थित कांशीराम कॉलोनी में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें 25 वर्षीय युवक मोनू को उसी के दोस्तों ने शराब पिलाने के बाद चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। इस हमले में मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है।

पीड़ित की माता सुषमी के अनुसार, मोनू सोमवार की रात करीब 10:30 बजे काम से घर लौटा था, तभी कॉलोनी में रहने वाले महताब अली और निहाल नामक युवकों ने उसे बुलाया और अपनी चौथी मंजिल की छत पर ले जाकर शराब पिलाई।

आरोप है कि मोनू के पास मौजूद 40 हजार रुपये लूटने के बाद दोनों ने उसे छत से नीचे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक आर.के. राणा ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, खबर लिखे जाने तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत लालपुर करौता की गलियों में बह रहा कीचड़

» ग्राम प्रधान और सचिव ने कागजों पर कराए विकास कार्य, सरकारी धन का हुआ है बंदरबाट

स्वराज इंडिया संवाददाता

सूरतगंज (बाराबंकी)। ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत लालपुर करौता गांव में घरों से निकलने वाला गंदा पानी बीच रोड पर बह रहा है। जिसके चलते जलजमाओ व भारी गड्ढे होते जा रहे है जिससे गांववासियों के साथ राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है इस ओर न ग्राम प्रधान ध्यान दे रहे है न जिम्मेदार अधिकारी , जबकि ग्रामीणों का कहना है कि 16 मई को इस समस्या को लेकर खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अवगत करा चुके हैं। जिससे इस समस्या से निजाज पाया जा सके और दर्जनों ग्रामीणों ने नाली निर्माण की गुहार लगाई है।

लोगो का कहना है कि गांव के घरों का पानी नालियों से होकर आगे नाली न होने के कारण बीच रास्ते पर गांव के घरों का गंदा पानी बहरहा है जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पानी निकासी के लिए आगे की नाली निमार्ण या फिर नाला निर्माण की गुहार लगा रहे है। ग्रामणी कल्लू, तस्ववर, जमशेद , मुरादी, शेष मिश्रा, रफी, रहीमुद्दीन, अहिमुद्दीन का कहना है कि घरों से निकल रहा गंदा पानी सड़क पर जम रहा है। इससे आमजन मानस को परेशानी उठानी पड़ रही है। जबकि रात के अंधेरे में कई कई लोग गिरकर चोटिल हो जा चुके हैं। साथ ही रोड पर गंदे पानी फैलने से मच्छर भी पनपने लगे हैं। स्थानीय निवासी का कहना है कि राहगीर आए दिन फिसलकर गिर जाते हैं। जब तक नाली नहीं बनेगी। यह समस्या बढ़ती ही रहेगी। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से लेकर सूरतगंज ब्लांक में कई बार कर चुके है लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। जिससे आवागमन करने वालो के लिए सबब बना हुआ है। इस संबंध में सूरतगंज खंड विकास अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह से बताया मामला हमारे जानकारी में नही है। वही इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वसीम ने बताया कि यह नाला निर्माण सांसद या ब्लॉक प्रमुख की निधि से ही बन सकता है हमारे पास इतना बजट नही है।

यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए बनेगा स्पेशल आयोग

निर्मल तिवारी/ स्वराज इंडिया

लखनऊ। यूपी में अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए डेडिकेटेड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आयोग ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट के मानकों के आधार पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगा। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले निकाय चुनावों में भी आयोग का गठन किया गया था।

» यूपी के पंचायती राज विभाग ने शुरू कर दी कवायद

» इससे पहले निकाय चुनावों में भी इसी तरह से आयोग का गठन किया गया था

» वर्ष 2026 में पंचायत चुनाव प्रस्तावित किए गए हैं

प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग एवं राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगरीय निकायों के सृजन व विस्तार पर रोक लगाई जा चुकी है और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा। इसके बाद पंचायतों में रोटेशन के आधार पर आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा।

आयोग इसलिए जरूरी बताया...

एससी-एसटी आरक्षण के लिए तो जनगणना को आधार बनाया जाता है। यानी 2011 के आंकड़ों के आधार पर इसका निर्धारण होगा। लेकिन, ओबीसी आरक्षण के लिए संक्षिप्त सर्वे करवाए जाने की परंपरा रही है। 27फीसदी पद ओबीसी के लिए आरक्षित होते हैं। हालांकि, महाराष्ट्र के एक मामले में सुप्रीम

कोर्ट ने साफ कह दिया कि ओबीसी आरक्षण के लिए भी एक तय प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसे ट्रिपल टेस्ट का नाम दिया गया।वर्ष 2023 में यूपी में भी निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के लिए परंपरागत फॉर्म्युले को ही अपनाया गया था। बाद में सरकार ने आयोग का गठन किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की, फिर चुनाव करवाया गया था। पंचायत चुनाव के दौरान तकनीकी एवं कानूनी अड़चनों को लेकर सरकार पहले से ही सतर्क है। इसलिए, आयोग के गठन की तैयारी है।

पंचायतों में उन वर्गों को प्राथमिकता मिलेगी जिनको अभीतक लाभ नहीं मिला

सूत्रों के अनुसार, ओबीसी के आरक्षण के अलावा अन्य संवर्गों के रोटेशन के आधार पर आरक्षण के दौरान भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पंचायतों में उन वर्गों को प्राथमिकता मिले जिनको अभी लाभ नहीं मिला है। 2021 के पंचायत चुनाव में 1995 को आधार वर्ष मान आरक्षण लागू करने की कवायद हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने वर्ष 2015 के रोटेशन के आधार पर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। सूत्रों की मानें तो इस बार इन बिंदुओं पर भी होमवर्क किया जा रहा है, जिससे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो पंचायतें अभी तक आरक्षित नहीं हुई हैं उनको भी दायरे में लाया जा सके।

बसपा प्रमुख मायावती ने सुरक्षा का हवाला देते हुए छोड़ा बंगला

» मायावती ने चुपचाप अपना 35, लोधी एस्टेट वाला बंगला खाली कर चाभी सीपीडब्लूडी को भेज दी

» मायावती लगभग एक साल पहले ही इस बंगले में आई थी

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। बसपा प्रमुख मायावती ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपना नई दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली कर दिया है। लगभग एक साल पहले उन्हें यह आवास आवंटित किया गया था। बताया जा रहा है कि मायावती ने 20 मई को बंगला खाली कर दिया। बंगले के पास स्कूल होने के कारण सुरक्षा में दिक्कतें आ रही थीं।

करीब 10 साल पहले भी मायावती ने अपनी सुरक्षा को खतरा बताया था, तब उनके लुटियंस दिल्ली स्थित बंगले के सामने से एक बस स्टॉप हटवा दिया गया था। अब BSP ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और मायावती ने चुपचाप अपना 35, लोधी एस्टेट वाला बंगला खाली कर दिया। मायावती लगभग एक साल पहले ही इस बंगले में आई थीं। यह बंगला उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष होने के नाते मिला था। उन्होंने 20 मई को बंगला छोड़ दिया और चाबियां CPWD (सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) को सौंप दी हैं।एक अंग्रेजी न्यूज पेपर में छपी रिपोर्ट के अनुसार, 35, लोधी एस्टेट, BSP प्रमुख के लिए एकदम सही जगह थी, क्योंकि उन्हें ‘-प्लस सुरक्षा मिली हुई थी। यह बंगला पार्टी के केंद्रीय कार्यालय, 29, लोधी एस्टेट के ठीक पीछे वाली लेन में स्थित था। पार्टी कार्यालय का पिछला गेट 35, लोधी एस्टेट की ओर खुलता था। पिछले साल दोनों बंगलों का एक जैसा नवीनीकरण किया गया था। मायावती के घर बदलने के फैसले पर क्स्क के वरिष्ठ पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।

मानदेय वृद्धि नहीं होने से एमडीएम समन्वयक और कंप्यूटर ऑपरेटर नाराज

लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर कहा कि समन्वयक व कंप्यूटर ऑपरेटरों का पिछले 10 वर्षों से मानदेय नहीं बढ़ा

वरिष्ठ संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम) समन्वयक व कंप्यूटर ऑपरेटरों का पिछले 10 वर्षों से मानदेय नहीं बढ़ा है। इससे इनमें नाराजगी है। अपनी मांगों को लेकर समन्वयक व ऑपरेटर 26 मई को प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन करने पहुंचे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने संगठन के पदाधिकारियों को बुलाकर उनसे वार्ता की एवं आश्वासन दिया कि निदेशक एवं वित्त नियंत्रक बेसिक से वार्ताकर शीघ्र ही मानदेय वृद्धि किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश स्तरीय संगठन मध्यान्ह भोजन समन्वयक, कंप्यूटर ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि एमबीए व एमसीए जैसी उच्च डिग्रीधारी समन्वयक व ऑपरेटर बेसिक शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं फिर भी उन्हें 10 वर्षों से वेतन वृद्धि नहीं मिली है। संघ का दावा है 2012 के दस प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रस्ताव को लागू रखा गया होता तो समन्वयकों को लगभग 75 हजार और ऑपरेटरों को 38 हजार मासिक मानदेय मिल रहा होता। देहात से मंजीत, गणेश श्रीवास्तव, नरेन्द्र कुमार, देवर्षि बाजपेई, निधी शर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे।